तिब्बत देश

# तिब्बत पर चीन का एकमात्र विकल्प : बातचीत

तिब्बत में चीन विरोधी प्रदर्शनों का न थमने वाला दौर अब बीजिंग सरकार के लिए गंभीर सिरदर्द बनता जा रहा है। शुरू–शुरू के दौर में ही वहां भारी संख्या में सेना की नई ताकत झोंककर, मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसे संचार साधनों को बंद करके और वहां मौजूद विदेशी पर्यटकों और अन्य विदेशियों को बाहर निकालकर चीन सरकार ने तिब्बती प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण पाने की जो मुस्तैदी दिखायी वह सब काफी प्रभावशाली था। लेकिन इससे पहले कि बीजिंग के शासक अपनी सेना की इस उपलब्धि पर चैन की सांस ले पाते तिब्बती जनाक्रोश की यह आग उन तिब्बती इलाकों में भी फैल चुकी है जहां से चीनी शासकों को इसकी कभी आशंका भी नहीं रही होगी। इनमें से कुछ इलाके तो ल्हासा से ढाई हजार किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हैं।

पिछले एक महीने के दौरान इन इलाकों में पचास से भी अधिक स्थानों पर चीन विरोधी प्रदर्शन हो चुके हैं जिन्हें दबाने के लिए चीनी सेना की कार्रवाई में 200 से ज्यादा लोगो के मरने की आशंका है। इन इलाको में तिब्बती असंतोष न केवल अभी भी जारी है बल्कि चीनी विरोध के ये स्वर अब चीनी राजधानी बीजिंग समेत उन विश्वविद्यालयों में भी उठने शुरू हो चुके हैं जहां चीनी रंग में रंगने के लिए तिब्बती विद्यार्थियों को भेजा जाता है। ताज़ा समाचारों के अनुसार चीनी बुद्धिजीवियों के कई संगठनों और मुखर हस्तियों द्वारा तिब्बत में चीन सरकार की दमन नीति की खुलकर आलोचना ने अब यह आशंका पैदा कर दी है कि तिब्बत से शुरू हुआ यह आंदोलन 1989 के लोकतंत्र आंदोलन से भी ज्यादा विकराल रूप ले सकता है।

चीन के भीतर से सुलग रही विद्रोह की इस आग का एक गंभीर पहलू यह है कि तिब्बत के समर्थन में इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह के विरोध के स्वर उठ रहे हैं वे बीजिंग के कम्युनिस्ट शासकों के लिए बहुत अशुभ सिद्ध हो सकते हैं। खासकर बीजिंग–ओलंपिक के लिए जिसे चीन सरकार प्रतिष्ठा का प्रश्न बना चुकी है। चीन पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ इस बात पर लगभग एकमत हैं कि बीजिंग सरकार की सेना में तिब्बत और चीन के भीतर उठने वाली विद्रोह की आवाजों को दबाने की व्यापक ताकत है। लेकिन वे इस बात पर भी सहमत हैं कि अब दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति के ताने बाने में चीनी व्यवस्था जिस गहराई तक जुड़ चुकी है उसे देखते हुए अब चीन के कम्युनिस्ट शासकों के विकल्प बुरी तरह सीमित हो चुके हैं।

1989 मार्च में ल्हासा में और उसी साल जून में बीजिंग के थिएन अनमन चौक में चीनी सेना ने जिस प्रभावकारी तरीके से तिब्बती जनता और चीनी युवाओं के दोनों आंदोलनों को फौजी टैंकों के बूते पर नियंत्रित किया था उसका लाख विरोध करने पर भी विश्व जनमत चीनी शासकों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। बल्कि सच तो यह है कि संचार साधनों पर चीन सरकार के लगभग एकछत्र नियंत्रण के कारण इन दोनों चीनी कार्रवाइयों के बारे में दुनिया को केवल आधी अधूरी जानकारी ही मिल पायी थी और आंदोलनकारियों के साथ तो वह नाममात्र का संपर्क भी नहीं बना पायी थी। इससे पहले 1951 में तिब्बत पर चीन का कब्जा होने और 1959 में चीनी सेना के खिलाफ तिब्बती जनक्रांति के दौर में घटी घटनाओं की जानकारी हासिल करने में तो बाहरी दुनिया को महीनों, बल्कि कुछ मामलों में कई बरस लग गए थे। इस कारण किसी अंतर्राष्ट्रीय दखल से पहले ही चीन सरकार हर चीज पर अपना नियंत्रण बना चुकी थी और संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया की कोई भी ताकत कुछ नहीं कर पायी थी।

लेकिन चीनी शासक अब अचानक यह देखकर परेशान हैं कि 2008 की दुनिया बहुत बदली हुई है। 17 मार्च के दिन जिस समय बीजिंग में चीनी सरकार का प्रवक्ता विदेशी पत्रकारों के सामने तिब्बत में प्रदर्शनों पर काबू पा लेने का दावा कर रहा था, ठीक उसी समय ल्हासा से ढाई हजार किलोमीटर दूर गांसू प्रांत के कीर्ति मठ का एक भिक्षु अपने मोबाइल फोन पर धर्मशाला में बैठे लगभग 50 विदेशी पत्रकारों को वहां जमीन पर पड़ी 15 तिब्बती प्रदर्शनकारियों की लाशों और मठ के बाहर तैनात 77 चीनी सैनिक ट्रकों की गिनती बता रहा था। जिस समय यह तिब्बती भिक्षु इन संवाददाताओं के प्रश्नों के उत्तर दे रहा था उस समय शरणार्थी भिक्षुओं की एक टोली संवाददाता सम्मेलन कक्ष के बोर्ड पर उन लाशों और आसपास जमा भीड़ के वे फोटो चिपका रही थे जो उन्होंनें कुछ मिनट पहले ही कीर्ति मठ से आई ई–मेल में से डाउनलोड किए थे।

तिब्बत में लाकर बसाए गए लाखों हान चीनी नागरिकों को मिली इंटरनेट, मोबाइल, अंतराष्ट्रीय फोन और तेज संपर्क सड़कों ने वहां तिब्बतियों को भी अपने आंदोलन को संगठित करने और विदेश में अपने समर्थकों से संपर्क बनाने की सुविधाएं दे दी हैं। यही कारण है दुनिया की जनता इस बार प्रदर्शनकारियों के मोबाइल और इंटरनेट से डाउनलोड की गई लाइव फुटेज को अपने टीवी और वेबसाइटों पर देख पा रही थी।

इस टैक्नोलाजी क्रांति ने दुनिया के साथ संपर्क के मामले में हर तरह के हथियार और सुविधाओं से लैस चीन की लाल–क्रांति सरकार और निहत्थे तिब्बती नागरिकों को बराबरी के स्तर पर ला खड़ा किया है। ऐसे में यह देखकर किसी को हैरानी नहीं हो रही कि प्रदर्शनकारी तिब्बती जनता को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। अब ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, पोलैंड, और न्यूज़ीलैंड जैसी वे दर्जनों संसदें और सरकारें भी प्रस्ताव पारित करके तिब्बत में अंतर्राष्ट्रीय जांच दल भेजने की मांग करने लगी हैं जो चीन सरकार की व्यापारिक धमकियों के आगे चुप्पी साध लिया करती थीं। यहां तक कि चीन के मामलों में नैतिक साहस दिखाने की परंपरा भूल चुके संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और मानवाधिकार काउंसिल ने भी चीन को नसीहतें देनी शुरू कर दी हैं। 23 मार्च को यूरोपीय संसद अध्यक्ष हांस गेर्ट पोट्रिंग ने तो बीजिंग को सीधी धमकी दे दी है कि अगर उसने तिब्बत समस्या के हल के लिए दलाई लामा से बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया तो पूरी यूरोपीय बिरादरी बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार कर सकती है।

लेकिन दलाई लामा के लिए 'भिक्षु के चोगे में लिपटा भेड़िया' जैसी गाली गलौज भरी भाषा का इस्तेमाल करने वाली बीजिंग सरकार के सामने इससे भी बड़ा संकट घर के भीतर से शुरू हो चुका है। पहले 17 मार्च के दिन चीन के शानडोंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और मुखर विद्वान सुन वेन गुआंग ने नेशनल पीपल्स कांग्रेस और चाइनीज़ पीपल्स पोलिटिकल कंसलटेटिव कमेटी को खुला पत्र लिखकर मांग की कि वह तिब्बती प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकारी हिंसा बंद कराएं और तिब्बतियों के खिलाफ सरकारी टीवी पर दुष्प्रचार बंद करें। उसके तुरंत बाद चीन के 22 प्रमुख मानवाधिकार समर्थक बुद्धिजीवियों ने खुला पत्र जारी करके तिब्बत में चीन सरकार की हिंसा की निंदा की है।

बीजिंग सरकार के सामने सांप छछूंदर वाली स्थिति पैदा हो गई है। खुली संचार व्यवस्था में अब अपनी सरकारी हिंसा को वह न तो छिपा सकती है और न अपनी हेकड़ी में उसे रोकने का साहस ही रखती है। अपने ही बनाए इस चक्रव्यूह से निकलने का सबसे आसान रास्ता यही है कि वह दुनिया की सलाह मानकर दलाई लामा से बातचीत शुरू करे और तिब्बत का शांतिपूर्ण हल निकाले। लेकिन इस सबके लिए उसे वह नैतिक साहस बटोरना होगा जो चीन के 60 साल के इतिहास में पहले कभी नहीं दिखाई दिया। किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर इस टकराव का पहला शिकार बीजिंग ओलंपिक हो। अगर ऐसा होता है तो यह चीन के वैसे ही खात्मे की शुरूआत सिद्ध हो सकता है जैसा सोवियत संघ के मामले में हुआ था।

— विजय क्रान्ति

फोटो : विजय क्रान्ति

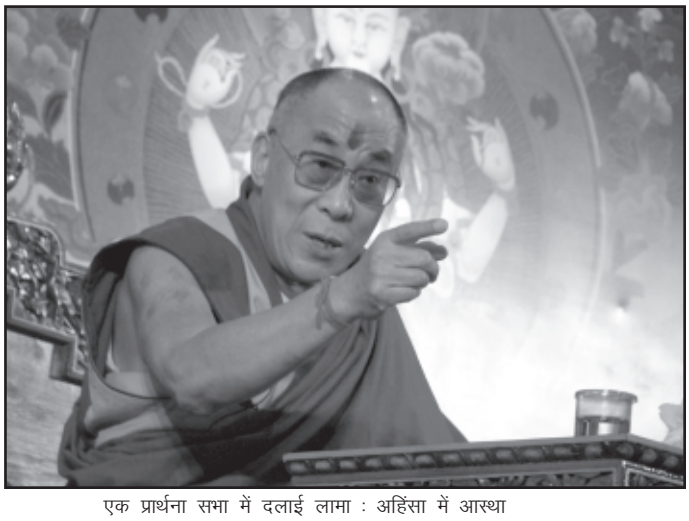

एक प्रार्थना सभा में दलाई लामा : अहिंसा में आस्था

# हमारा संघर्ष चीनी नेताओं के साथ है, चीनी जनता के साथ नहीं

## दलाई लामा ने तिब्बती जनता के संघर्ष की प्रशंसा की पर इसे अहिंसक रखने पर बल दिया

*6 अप्रैल के दिन परमपावन दलाई लामा द्वारा तिब्बत में और निर्वासन में रहने वाली तिब्बती जनता के नाम विशेष पत्र जारी किया। यहां वह पत्र प्रस्तुत है।*

*म्युनिस्ट पार्टी के बहुत से तिब्बती सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों ने इस तनावग्रस्त स्थिति में भी जिस साहस के साथ अपनी तिब्बती पहचान को भूले बिना सही और गलत में भेद करते हुए सत्य का पक्ष लिया है मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।*

तिब्बत के तीनों प्रांतो के सभी तिब्बतियों के प्रति संवेदना सहित अभिवादन प्रकट करते हुए मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं।

1. 10 मार्च से लेकर अब तक न केवल समस्त तिब्बत के क्षेत्रों में बल्कि चीन के शहरों में रह रहे विद्यार्थियों ने भी यह बताने के लिए प्रदर्शन किए हैं कि लंबे समय से हो रहे मानवाधिकार एवं धार्मिक स्वतंत्रता के हनन और वास्तविकता से हटकर निरा धार तथ्यों के प्रचार करने के कारण तिब्बत की जनता असंतुष्ट है पर फिर भी चीन सरकार असत्य को किसी न किसी तरह सत्य के रूप में प्रस्तुत करने का हर संभव प्रयास करती आ रही है। उदाहरण के लिए तिब्बतियों से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को भगवान बुद्ध के अवतार की तरह मानने के लिए कहना एकदम वामपंथी और हान चीनी दादागीरी जैसा लगता है। इस परिस्थिति में तिब्बती जनता ने बेबस और लाचार होने के कारण शांतिपूर्वक विरोध के माध्यम से जब अपनी भावनाओं को उजागर किया तब उन पर जिस प्रकार से चीन सरकार ने हथियारों का प्रयोग किया उसके कारण अनेक तिब्बतियों की जानें गईं हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं और असीमित अत्याचार हुए हैं। इसे देखते हुए निस्संदेह किसी भी करुणायुक्त व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस पर अत्यंत व्याकुलता और संवेदना व्यक्त करते हुए भी मैं स्वयं को इस स्थिति में असमर्थ पा रहा हूं।

2. इस जन आंदोलन में मारे गए उन सभी तिब्बती एवं चीनी नागरिकों के प्रति मैं अपने मन से निरंतर प्रार्थना करता हूं।

3. चीनी सरकार हमेशा यह कहती आ रही है कि कुछ अल्पसंख्यक असंतुष्ट तिब्बतियों को छोड़कर अधिकांश तिब्बती इस शासन से संतुष्ट हैं। इसे सिद्ध करने के लिए वास्तविकता के विपरीत विभिन्न प्रकार का प्रचार किया जा रहा है जिसकी सच्चाई से अब परदा हट चुका है। यह स्पष्ट हो गया है कि तिब्बत के विषय को दुनिया नजरंदाज नहीं कर सकती। चीन और तिब्बत दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए वास्तविकता के आधार पर सत्य के रास्ते से इस समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। जिन तिब्बती नागरिकों ने अपने देशवासियों के कल्याण के लिए अपने मन में दबी हुई उन गहरी भावनाओं को साहस और दृढ़ निश्चय के साथ बलिदान देकर प्रकट किया है वे प्रशंसा के पात्र हैं। दुनिया की जनता ने उनकी इस भावना की सराहना की है।

4. कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत से तिब्बती सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों ने इस तनावग्रस्त स्थिति में भी जिस साहस के साथ अपनी तिब्बती पहचान को भूले बिना सही और गलत में भेद करते हुए सत्य का पक्ष लिया है मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार के तिब्बती सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि भविष्य में भी वे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के बजाए समस्त तिब्बत की जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मुद्दों को अधिकारियों के सामने रखें और आम तिब्बतियों को निष्पक्ष रूप से सही मार्गदर्शन दें।

5. संपूर्ण दुनिया के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, विदेश मंत्रियों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं, संसद सदस्यों और आम नागरिकों ने तिब्बत की वर्तमान हालत के बारे में अपनी संवेदना प्रकट करते हुए न केवल चीन सरकार के नेताओं से इसे रोकने का आह्वान किया है बल्कि इस समस्या का हल निकालने के लिए भी अनुरोध किया है। हमें इन लोगों के प्रयासों का फल प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। मुझे इस बात की जानकारी है कि आप सभी ऐसी परिस्थिति में रह रहे है जहां हर तरफ आक्रोश उत्पन्न हो सकता है लेकिन फिर भी हम सभी को अहिंसा की विचारधारा के अनुकूल दृढ़ता से व्यवहार करना होगा।

6. चीनी लोक गणराज्य के नेता हाल के दिनों में हुए प्रदर्शनों के पीछे मेरे और निवार्सित प्रशासन के हाथ होने के बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। इस पर मैं चाहता हूं कि स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय जांच कर्ताओं के माध्यम से इन आरोपों की जांच हो जिससे सच और झूठ सामने आए। यदि चीनी लोक गणराज्य के पास इन आरोपों को सिद्ध करने के लिए तथ्य एवं सबूत हों तो मनमाने आरोप लगाने के बजाए उन्हें इस सबूतों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करना चाहिए।

7. जैसा कि सभी को मालूम है मैंने तिब्बती नागरिकों के भविष्य का ध्यान रखते हुए तिब्बत को चीनी लोक गणराज्य की छत्रछाया के अन्तर्गत रहकर तिब्बत की समस्या का हल निकालने का प्रस्ताव रखा है। 1974 से लेकर अब तक मैंने दोनों की हितों को ध्यान में रखते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है। मध्यम मार्ग का अर्थ है कि समस्त तिब्बती नागरिक एक ही तरह के प्रशासनिक ढांचे में रह पायें जिसे वास्तविक तौर पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्वायत्तता प्राप्त हो जिसमें विदेशी और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मामलों को छोड़कर बाकी सभी तरह के स्वशासन और अपने बारे में फैसले करने की सुविधा उपलब्ध हो। मैं शुरू से ही कहता आया हूं कि अपने और तिब्बत के बारे में फैसला करने का अंतिम अधिकार केवल तिब्बती जनता का है।

8. इस साल बीजिंग में होने जा रही ओलम्पिक खेल प्रतिस्पर्धाएं एक सौ बीस करोड़ चीनी जनता के लिए हर्ष और गर्व का विषय है। मैं शुरु से ही इन खेलों के बीजिंग में आयोजन का समर्थक रहा हूं। इस बारे में मेरी राय बदली नहीं है। मैं यह मानता हूं कि तिब्बतियों को इसमें किसी तरह की बाधा नहीं डालनी चाहिए। हर तिब्बती को अपनी आजादी और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का अधिकार है। लेकिन दूसरी ओर अगर हममें से कोई कुछ ऐसा करता है जिससे चीनियों के मन में घृणा पैदा हो तो इसका परिणाम उलटा होगा। एक मैत्रीभावयुक्त सामाज की रचना के लिए हमें अपने मन में विश्वास और सम्मान पैदा करने की जरूरत है जो ताकत के प्रदर्शन या धमकाकर नहीं हासिल किया जा सकता।

9. हमारा यह संघर्ष चीनी लोक गणराज्य के कुछ गिनेचुने राजनैतिक नेताओं से है, न कि चीनी नागरिकों से। हमें ऐसा कोई भी कदम उठाने से सावधान रहना चाहिए जिसके कारण बहुसंख्यक चीनी नागरिकों के मन में द्वेष पैदा हो। इस मुश्किल परिस्थिति में भी चीन के भीतर एवं बाहर रह रहे चीनी बुद्धिजीवियों, लेखकों एवं वकीलों की तरफ से जिस प्रकार के समर्थन भरे वक्तव्य, लेख एवं अन्य सहायता के आश्वासन दिए गए हैं इससे निश्चित रूप से हमें सहानुभूति एवं प्रोत्साहन मिला है। मैंने 28 मार्च के दिन समस्त विश्व में रह रहे चीनी नागरिकों के लिए एक अपील और संदेश जारी किया है। मुझे आशा है कि आप भी इसे सुनेंगे या पढ़ेंगे।

10. यदि यह स्थिति निरन्तर रहती है तो मुझे डर है कि हमारे ऊपर चीन सरकार का हिंसक दमन भी और अधिक बढ़ सकता है। मैं इससे बहुत चिन्तित हूं। मेरा यह नैतिक दायित्व है कि ऐसी स्थिति न पैदा हो। इसलिए मैंने चीनी लोक गणराज्य के सम्बन्धित नेताओं से लगातार यह अनुरोध किया है कि समस्त तिब्बत में अपने हिंसक दमन को रोकें और तिब्बत से अपने सुरक्षा बलों एवं सैनिकों को हटाएं। यदि मेरे इन प्रयासों के सार्थक परिणाम निकलते हैं तो मैं तिब्बती जनता से भी आग्रह करूंगा कि वे अपने वर्तमान प्रदर्शनों को रोक दें।

11. मैं स्वतन्त्र देशों में रहने वाले तिब्बतियों से भी आग्रह करूंगा कि तिब्बत की भीतरी स्थिति के विषय में अपनी भावनाएं व्यक्त करते समय उन्हें विषेश सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वे ऐसा कोई भी कार्य न करें जिसे हिंसक कहा जा सके। हमें भड़काए जाने की कठिनतम परिस्थितियों में भी हमें अपने अमूल्य मूल्यों का त्याग नहीं करना है। अहिंसा के मार्ग से हमें सफलता मिलेगी, इसमें मैं पूरी निष्ठा रखता हूं। हमें इस बात का भी पूरी तरह का ध्यान रखना है कि हम उन लोगों के प्रति भी जवाबदेह हैं जिनसे हमें अभूतपूर्व प्यार और समर्थन मिल रहा है।

12. तिब्बत के दरवाज़े इस समय बंद हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के लिए बंद कर दिया गया है। मुझे शंका है कि मेरा यह संदेश समस्त तिब्बतियों तक पहुंच पायेगा या नहीं। लेकिन मुझे विश्वास है कि मीडिया और एक दूसरे के माध यम से आप अधिकांश लोगों तक मेरी यह बात अवश्य पहुंचेगी।

13. अन्त में, पुनः मैं आप तिब्बतियों से इस बात को दोहराना और अपील करना चाहता हूं कि आप अहिंसा के मार्ग पर कायम रहें और किसी भी तरह की खराब स्थिति में भी इस मार्ग का त्याग न करें।

**दलाई लामा**
धर्मशाला 6 अप्रैल, 2008
(मूल तिब्बती से अनुवादित)

*यदि यह स्थिति निरन्तर रहती है तो मुझे डर है कि हमारे ऊपर चीन सरकार का हिंसक दमन भी और अधिक बढ़ सकता है। मैं इससे बहुत चिन्तित हूं। मेरा यह नैतिक दायित्व है कि ऐसी स्थिति न पैदा हो। इसलिए मैंने चीनी नेताओं से लगातार यह अनुरोध किया है कि समस्त तिब्बत में अपने हिंसक दमन को रोकें और तिब्बत से अपने सुरक्षा बलों एवं सैनिकों को हटाएं। यदि मेरे इन प्रयासों के सार्थक परिणाम निकलते हैं तो मैं तिब्बती जनता से भी आग्रह करूंगा कि वे अपने वर्तमान प्रदर्शनों को रोक दें।*

# संयुक्त राष्ट्र तिब्बत में अंतर्राष्ट्रीय जांच मिशन भेजे

## भारत का तिब्बत समर्थक सर्वदलीय संसदीय मंच

*ये तिब्बती प्रदर्शन वहां की जनता की इस भावना को दिखाते हैं कि वह चीन के दमनकारी शासन से मुक्ति पाना चाहती है। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाली तिब्बती जनता के प्रति एकजुटता और समर्थन व्यक्त करते हैं। भारत का तिब्बत समर्थक सर्वदलीय मंच चीन सरकार द्वारा तिब्बती जनता के निरंतर दमन और पहले से भी ज्यादा गंभीर अत्याचारों की निंदा करता है। यह मंच तिब्बत में गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों और अन्य लोगों की रिहाई की मांग करता है।*

नई दिल्ली, 16 मार्च भारतीय संसद के 48 सांसदों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि तिब्बत के भीतर की हालत के बारे में विश्व को सही जानकारी देने के लिए वहां एक अंतराष्ट्रीय जांच दल भेजा जाना चाहिए। भारत के तिब्बत समर्थक सर्वदलीय संसदीय मंच की ओर इस बयान में इन सांसदों ने कहा है कि यह मंच तिब्बत के कई भागों से चीनी नीतियों के खिलाफ तिब्बती लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों, उनकी हत्या, उनके घायल होने तथा गिरफ्तारियों के बारे में लगातार आने वाले समाचारों से बहुत चिंतित है। ये तिब्बती 10 मार्च को तिब्बत की जनक्रान्ति की 49वीं वर्षगांठ के दिन से केवल अपनी बात कहने और सभा करने की आजादी का इस्तेमाल करने के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं।

ये तिब्बती प्रदर्शन वहां की जनता की इस भावना को दिखाते हैं कि वह चीन के दमनकारी शासन से मुक्ति पाना चाहती है। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाली तिब्बती जनता के प्रति एकजुटता और समर्थन व्यक्त करते हैं। भारत का तिब्बत समर्थक सर्वदलीय मंच चीन सरकार द्वारा तिब्बती जनता के निरंतर दमन और पहले से भी ज्यादा गंभीर अत्याचारों की निंदा करता है। यह मंच तिब्बत में गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों और अन्य लोगों की रिहाई की मांग करता है।

यह मंच भारत सरकार से आग्रह करता है कि वह चीन सरकार को इस बात के लिए मनाने की पहल करे कि वह परमपावन दलाई लामा के साथ अर्थपूर्ण बातचीत करके तिब्बत समस्या का हल निकाले। हम संयुक्त राष्ट्र और विश्व समुदाय से भी अपेक्षा करते हैं कि ल्हासा में और तिब्बत के दूसरे इलाकों में वहां की स्थिति की जांच के लिए एक विशेष अंतराष्ट्रीय मिशन भेजे और चीन के शासकों को तिब्बत में हालत सामान्य बनाने के लिए कहे। इस बारे में और अधिक देरी होने से हालात और बिगड़ेंगे।

इस संसदीय मंच के संयोजक श्री बशिष्ठ नारायण सिंह (राज्यसभा), सुश्री प्रतिभा सिंह (लोकसभा), श्री एम ए खराबेला स्वेन (लोकसभा) और श्री मोहन सिंह (लोकसभा) हैं। सदस्यों में चीन समर्थक कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़कर सभी दलों के सदस्य हैं।

# तिब्बत पर भारत की चुप्पी शर्मनाक और आत्मसमर्पण जैसी

## – जार्ज फर्नांडीज़

नई दिल्ली, 16 मार्च भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और तिब्बत के पुराने मित्र श्री जार्ज फर्नाडीज़ ने तिब्बत की स्थिति पर अपने बयान में कहा है कि यह शर्म की बात है कि भारतीय संसद ने अभी तक उस युद्ध के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का प्रयास तक नहीं किया है जो आज चीन ने तिब्बती जनता और उसकी संस्कृति, भाषा, धर्म और ऐसी हर चीज को बर्बाद करने के लिए चलाया हुआ है जो तिब्बती है। भारत के मार्क्सवादियों और कांग्रेस ने बिना कोई प्रयास किए ही चीन के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। मैं अपने सभी सांसद साथियों से अपील करता हूं कि वे तिब्बती मांगों की सुनवाई के समर्थन में उठ खड़े हों ताकि सुनवाई, सम्मानपूर्वक व्यवहार तथा सहानुभूति भरे व्यवहार की उनकी मांग पूरी हो सके।

जबकि पिछले कुछ दिन से दुनिया भर के देश चीनियों को सद्‌बुद्धि देने का प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार ने तो चुपचाप आत्मसमर्पण ही कर दिया है। मैं इस सरकार से, जो कभी चीनियों से कुछ कहने का साहस भी नहीं रखती, यह पूछना चाहता हूं कि तब क्या होगा अगर चीन ने फिर से 1962 कर दिया? चीन ने भारत को पाकिस्तान की ओर से उत्तर से लेकर राजस्थान तक और उत्तर–पूर्व में ऐसे भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों को पैसा और हथियार देकर घेर रखा है जो भारत को तोड़ना चाहते हैं।

# संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएं

## भारत–तिब्बत मैत्री संघ की अपील

नई दिल्ली, 20 मार्च तिब्बत के भीतर शुरु हुए जनांदोलन के प्रति भारतीय जनता का समर्थन व्यक्त करते हुए भारत–तिब्बत मैत्री संघ ने 20 मार्च और 31 मार्च को विशेष वक्तव्य जारी करते हुए संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार दोनों से अपील की तिब्बत में चल रहे नरसंहार के प्रति अपनी उदासीनता को त्याग कर वे अपनी जिम्मेदारी निभाने का साहस दिखाएं।

यहां उपरोक्त वक्तव्य प्रकाशित किया जा रहा है:

आप जानते हैं कि चीन के करीब छह दशक की दासता और जुल्म के विरुद्ध तिब्बतवासियों ने 'करो या मरो' की भावना से आजादी के अपने संघर्ष को पिछले 10 मार्च से नया तेवर दिया है। अपनी आजादी

के लिए आवाज उठाना हर मनुष्य का नैसर्गिक अधिकार है। तिब्बती भाई–बहन अपने इसी अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, किंतु चीन के निरंकुश शासकों ने उनकी आाज सुनने और इतने तीव्र असंतोष के कारणों को समझने के बजाए खून और लोहे की नीति से आंदोलन को बर्बरता पूर्वक कुचलने की नीति अपनायी है। निहत्थे तिब्बतियों पर गोलीबारी की घटनाओं में अब तक 140 से अधिक लोगों के मरने की खबर है। *( अप्रैल अंत तक मरने वाले तिब्बतियों की संख्या 200 से ऊपर और गिरफ्तार लोगों की संख्या 5 हजार से ज्यादा हो चुकी थी – संपादक)।*

चीन की लाल सेना और पुलिस घर–घर में घुसकर लोगों को पकड़ रही हैं। बौद्ध मठों तक को बख्शा नहीं गया है। आवागमन पर रोक तथा घायलों के इलाज पर पाबंदी के कारण भारी संख्या में पुलिस की गोली से घायलों के मरने की खबरें आ रही हैं। ऐसी हालत में हमारा मानवीय कर्तव्य है कि हम चीन के विरुद्ध तिब्बतियों के आजादी के संघर्ष में साथ दें। भारत–तिब्बत मैत्री संघ का 31 मार्च को 'तिब्बत बचाओ दिवस' का आह्वान भारत सहित दुनिया के तमाम देशों को तिब्बती जनता के प्रति अपने दायित्व के निर्वाह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए है।

हम मांग करते हैं कि :

1. संयुक्त राष्ट्र संघ तत्कार एक निष्पक्ष जांच दल भेजकर ल्हासा सहित पूरे तिब्बत में चल रहे फौजी दमन की सच्चाई सामने लाए और चीनी नेताओं तथा दलाई लामा के बीच तिब्बत की समस्या के बातचीत द्वारा समाधान की पहल करे।
2. भारत सरकार अपने पड़ोसी देश तिब्बत में हो रहे जन–दमन पर कागज़ी दुख जाहिर करने के बजाए दलाई लामा और चीन सरकार को दिल्ली बुलाकर मध्यस्थता का ऐतिहासिक कर्तव्य पूरा करके तिब्बत के बारे में अपनी गलतियों का प्रायश्चित करे।

मैत्री संघ ने भारतीय नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने–अपने स्थान पर तिब्बत मुक्ति के लिए अपने तरीके से कार्यक्रम आयोजित कर उपरोक्त मांगों के लिए संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार पर दबाव बनाएं।

इसके अलावा मैत्री संघ ने एक पर्चा भी जारी किया जिसमें बताया गया है कि चीनी प्रशासन शांतिपूर्ण तिब्बती प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने के लिए अपने एजेंटों को भिक्षु वेश में गड़बड़ी करने को भेज रही है। संघ ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों को सीधे पत्र लिखकर तिब्बत के प्रति चिंताओं से उन्हें अवगत कराएं और समुचित कदम उठाने के लिए उनसे आग्रह करें।

## रीवा में अनशन और धरना

रीवा, मध्य प्रदेश से प्राप्त विवरण के अनुसार भारत तिब्बत मैत्री संघ की प्रदेश शाखा ने 31 मार्च के दिन विभिन्न नागरिक और मानवाधिकार संगठनों के सहयोग से स्थानीय घंटाघर चौक स्थित वेंकटरमण पार्क में सांकेतिक उपवास–धरना रखा। उसके बाद एक जुलूस निकालकर रीवा संभाग के उायुक्त श्री एस के वेद को भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेंट किया। इन संगठनों में नारी चेतना मंच, विंध्यांचल जन आंदोलन और समाजवादी जन परिषद प्रमुख थे।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय खरे के अनुसार ज्ञापन में कहा गया है कि चीन ने भारत और चीन के बीच एक स्वतंत्र और बफ़र देश तिब्बत पर जबरन कब्जा किया हुआ है। भारत सरकार को चीन सरकार द्वारा इन दिनों तिब्बती जनता पर दिए जा रहे जुल्मों का ध्यान दिलाते हुए आग्रह किया गया है कि भारत को तिब्बत के पड़ोसी धर्म का पालन करना चाहिए।

## सं. राष्ट्र घायलों की जान बचाए

### महाराष्ट्र के तिब्बती समाज द्वारा अपील

महाराष्ट्र के गोंदिया जिला की नोरग्येलिंग तिबेतन सेटलमेंट के नागरिक संगठनों और प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से जारी एक बयान में सं. राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रास और विश्व जनमत से अपील की है कि चीनी सेना की गोलियों और हिंसा से घायलों की जान बचाने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं।

स्थानीय तिब्बती विधानसभा, तिब्बती युवा कांग्रेस, तिब्बती महिला संघ और होम डिपार्टमेंट प्रतिनिधि की ओर से जारी की गई एक संयुक्त अपील में कहा गया है कि प्रदर्शनों में घायल सैंकड़ों तिब्बती प्रदर्शनकारियों की हालत चिंताजनक है क्योंकि चीनी प्रशासन ने अपने सभी अस्पतालों और डाक्टरों को चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों का इलाज करने के बजाए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाए। ऐसे में गंभीर रूप से घायल सैंकड़ों तिब्बती मौत से जूझ रहे हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल एजेंसियों से अपने निष्पक्ष कार्यकर्ताओं को तुरंत तिब्बत भेजने की अपील की गई है।

अपील में सं.रा. संघ, सरकारों और मानवाधिकार संगठनों से आग्रह किया गया है कि वे तिब्बत की स्थिति की निष्पक्ष आकलन करने के लिए वहां अपने प्रेक्षक भेजें।

*चीन की लाल सेना और पुलिस घर–घर में घुसकर लोगों को पकड़ रही हैं। बौद्ध मठों तक को बख्शा नहीं गया है। आवागमन पर रोक तथा घायलों के इलाज पर पाबंदी के कारण भारी संख्या में पुलिस की गोली से घायलों के मरने की खबरें आ रही हैं। ऐसी हालत में हमारा मानवीय कर्तव्य है कि हम चीन के विरुद्ध तिब्बतियों के आजादी के संघर्ष में साथ दें।*

# भारत सरकार चीन को रिझाने के बजाए तिब्बत पर आत्मसम्मान की नीति अपनाए

## बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का संयुक्त बयान

नई दिल्ली, 22 अप्रैल तिब्बत में प्रदशनों और चीनी सेना तथा पुलिस द्वारा तिब्बती नागरिकों पर की गई अंधाधुंध हिंसा से पैदा हुई स्थिति पर विचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की संसदीय समिति ने 22 अप्रैल के दिन नई दिल्ली में एक विशेष बैठक की। इस बैठक के बाद पार्टी के तीन वरिष्ठ नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री राजनाथ सिंह और श्री जसवंत सिंह ने कहा कि भाजपा को तिब्बत के भीतर हाल ही में हुई घटनाओं पर बहुत चिंता है।

चीन के सशस्त्र बलों द्वारा तिब्बती जनता की आवाज़ को कुचलने के लिए अंधाधुंध तरीके से हिंसा का इस्तेमाल किया जाना एक बहुत गंभीर घटना है। जिस तरीके से वहां प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर पूरे विश्व समाज ने चिंता जताई है।

ऐसे में जिस प्रभावपूर्ण तरीके से परमपावन दलाई लामा जी ने तिब्बत और तिब्बत की जनता के कष्ट और दर्द को व्यक्त किया है वह पूरे मानव समाज की आत्मा को जगाने के लिए काफी है।

इस संदर्भ में यह देखकर सचमुच शर्म आती है कि चीन सरकार द्वारा बेशर्म तरीके से इस्तेमाल की गई हिंसा के बारे में अपनी नाराजगी प्रकट करने के बजाए भारत सरकार ने चीन सरकार को रिझाने की नीति अपनायी है और ऐसा करते हुए भारत के आत्मसम्मान और भारतीय विदेश नीति की स्वतंत्रता की गरिमा के प्रति अपमानपूर्ण अनदेखी की है। समाचारों से पता चलता है कि परमपावन दलाई लामा जी की निकट भविष्य में दिल्ली यात्रा के दौरान भारत के उपराष्ट्रपति की प्रस्तावित यात्रा को भी रद्द कर दिया गया है। हमें समझ नही आ रहा है कि भारत सरकार भारत के राष्ट्रीय सम्मान को गिराने वाली और अनिश्चय से भरी ऐसी वीभत्स नीति क्यों अपना रही है जिससे भारत के आत्मसम्मान की उपेक्षा हो रही है। बीजेपी इसकी निंदा करती है और यूपीए से आशा करती है कि वह इस अतार्किक नीति का तर्क देश को समझाए।

भारत को चाहिए कि वह आज की स्थिति में अपनी चिंताओं को सही तरीके से, पूरे दम के साथ और बिना किसी लाग लपेट के प्रकट करे। ऐसा करके भारत न केवल उस तिब्बती बौद्ध संस्कृति और सभ्यता के समर्थन में खड़ा होगा जो भारत की अपनी है बल्कि उस सबके समर्थन में खड़ा होगा जो पूरी मानवता को भारत की देन है। यही आज हमारी पक्की जिम्मेदारी है और हमारा आज का 'धर्म' है।

*भारत को चाहिए कि वह आज की स्थिति में अपनी चिंताओं को सही तरीके से, पूरे दम के साथ और बिना किसी लाग लपेट के प्रकट करे। ऐसा करके भारत न केवल उस तिब्बती बौद्ध संस्कृति और सभ्यता के समर्थन में खड़ा होगा जो भारत की अपनी है बल्कि उस सबके समर्थन में खड़ा होगा जो पूरी मानवता को भारत की देन है। यही आज हमारी पक्की जिम्मेदारी है और हमारा आज का 'धर्म' है।*

## अंतर्राष्ट्रीय भारत–तिब्बत सहयोग समिति ने चिंता व्यक्त की

मेरठ, 3 अप्रैल तिब्बत मुक्ति साधना और तिब्बती शरणार्थी समाज के हित में काम करने वाली एक अग्रणी संस्था अंतर्राष्ट्रीय भारत–तिब्बत सहयोग समिति ने तिब्बती जनता के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए वहां चीन सरकार द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की है।

संगठन के महामंत्री डा. देवेंद्र कुमार पाल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार तीन अप्रैल के दिन मेरठ में आयोजित समिति की सभा में तिब्बत की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई और दो प्रस्ताव पारित किए गए। पहले प्रस्ताव में कहा गया है कि एक ओर तो परमपावन दलाई लामा ने तिब्बत के प्रश्न पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और ओलंपिक खेलों के बारे में भी अपने विचार स्पष्ट कर दिए हैं। उन्होंने यह कहकर अपना बड़प्पन दिखाया है कि ओलंपिक खेल भाईचारे और सौहार्द के प्रतीक हैं लेकिन दूसरी ओर चीन शांति से बातचीत के प्रस्ताव को भी अपराध मान रहा है। चीन को चाहिए कि वह परमपावन जी के शांतिपूर्ण बातचीत के रास्ते से तिब्बत की समस्या को हल करने के प्रस्ताव को स्वीकार करे।

दूसरे प्रस्ताव में कहा गया है कि तिब्बत की मूल समस्या यह है कि तिब्बत की संस्कृति और धर्म को नष्ट करने का चीन प्रयास कर रहा है। तिब्बती जनता के साथ मारपीट व अत्याचार करने के गलत तरीके को चीन सरकार द्वारा रोका जाना चाहिए। यह मानवाधिकारों का सरासर उल्लंघन है। तिब्बत और चीन का पड़ोसी होने के नाते भारत के भी हित में है कि इस क्षेत्र में शांति बनाए रखी जाए। इसके लिए समिति ने भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से चीन सरकार से आग्रह किया है कि वह तिब्बत में शांति और सौहार्द बनाने के लिए कदम उठाए।

इस सभा की अध्यक्षता डा. एस पी रस्तोगी ने की और कोर ग्रुप फार तिबेतन कॉज़ के राष्ट्रीय सह संयोजक और जाने माने गांधीवादी श्री कुल भूषण बख्शी ने तिब्बत की समस्या और वहां की मौजूदा हालत के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

# ओलंपिक समिति चीन सरकार के आगे दब्बूपन छोड़कर साहस दिखाए

## तिब्बत में मीडिया के अधिकारों के हनन पर दिल्ली पत्रकार संघ ने प्रस्ताव पारित किया

नई दिल्ली, 7 अप्रैल तिब्बत में चलने वाले घटनाचक्र में वहां चीन सरकार द्वारा मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों और इस कारण सही समाचारों पर पाबंदी से पैदा हुई स्थिति पर विचार करने के लिए दिल्ली पत्रकार संघ ने एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया। यह संघ भारत के सबसे प्रमुख राष्ट्रीय पत्रकार संगठन नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स (भारत) का सहयोगी संगठन है। सेमिनार के मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार और तिब्बती मामलों के विशेषज्ञ श्री विजय क्रान्ति थे। अध्यक्षता पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री मनोहर सिंह ने की।

अपने वक्तव्य में श्री विजय क्रान्ति ने तिब्बत की मौजूदा स्थिति का विस्तृत विष्लेषण प्रस्तुत करने के साथ–साथ तिब्बती समस्या की पृष्ठभूमि का भी विवरण दिया। उन्होंने बताया कि इस साल तिब्बती जनक्रान्ति की 49वीं सालगिरह के मौके पर पूरे तिब्बत में फैले प्रदर्शन कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थे। इस तरह के प्रदर्शन 1951 में तिब्बत पर चीन के कब्जा जमाने के बाद लगातार होते आए हैं। लेकिन इस बार पहला मौका था जब इंटरनेट और मोबाइल के कारण तिब्बती प्रदर्शनकारियों के उत्साह और चीनी सेना तथा पुलिस के अत्याचारों के समाचार, फोटो और वीडियो फुटेज पूरी दुनिया तक पहुंच पाए।

श्री क्रान्ति ने बताया कि तिब्बत में चीन सरकार का व्यवहार एकदम उपनिवेशवादी किस्म का होने के कारण पूरे तिब्बत की जनता के मन में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। ये प्रदर्शन इसी नाराजगी का विस्फोट थे। पिछले कुछ साल से चीन ने लाखों की संख्या में हान चीनियों को तिब्बत में बसाना शुरू कर दिया है। इस अभियान का लक्ष्य स्थानीय तिब्बतियों को अपने ही देश में एक अर्थहीन अल्पसंख्यक बनाकर तिब्बत की समस्या का 'अंतिम हल' निकालना है। इससे पहले चीन सरकार इस तरह के अभियान भीतरी मंगोलिया, पूर्वी तुर्किस्तान (सिंकियांग), मंचूरिया और ऐसे कई छोटे–छोटे देशों में चला चुकी है जिन पर हान चीनियों ने जबरन कब्जा करके उन्हें आज के विशाल और 'नए चीन' में मिला लिया था।

श्री क्रान्ति ने बताया कि तिब्बत पर कब्जे के कारण चीन को इतिहास में पहली बार दक्षिण एशिया के देशों के साथ साझा सीमा मिली है। इसका फायदा उठाकर चीन अब पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और बांग्लादेश के माध्यम से भारत के घेरने में लगा है। चीन तिब्बत के रास्ते भारत के खिलाफ सीधा सैनिक दबाव बनाने में लगा है और भारत में सक्रिय नक्सली और उत्तर–पूर्वी प्रांतों के अन्य देशद्रोही आतंकवादी संगठनों को भारत को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है।

सेमिनार में तिब्बत की वर्तमान स्थिति पर सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में चीनी सेनाओं द्वारा निहत्थे तिब्बती प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा के अंधाधुंध दुरूपयोग की निंदा की गई। चिंता व्यक्त की गई कि समाचारों को दुनिया के सभ्य समाज तक पहुंचने से रोकने के लिए चीन सरकार ने तिब्बत में विदेशी पत्रकारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है और विदेशी पर्यटकों को भी बाहर निकाल दिया है। पत्रकार संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की इस बात के लिए आलोचना की है कि वह ओलंपिक के नियमों की अवहेलना करके चीन सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर मनमाने प्रतिबंध लगाने की अनुमति देकर अपने दब्बूपन का प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे एक नियम के अनुसार टीवी चैनलों की लाइव फुटेज को पहले आठ मिनट तक लूप में चलाकर चीनी सुरक्षा एजेंसियां जांचेंगी और केवल तभी प्रसारण की अनुमति देंगी जब वे आश्वस्त हो जाएंगी कि इसमें किसी प्रदर्शनकारी या चीन विरोधी नारे वाला बैनर आदि नहीं दिखाया गया। सेमिनार में ये प्रस्ताव पारित किए गएः

1. चीन सरकार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और और नागरिक संगठनों के तिब्बत में प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस ले और उन्हें तिब्बत की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने तथा चीनी सेना की हिंसा में पीड़ित लोगों तक राहत और मैकिडकल सहायता पहुंचाने की अनुमति दे।

2. हम ओलंपिक समिति से आग्रह करते हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि ओलंपिक खेलों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर चीन सरकार ऐसा कोई अलोकतांत्रिक या मनमाना प्रतिबंध न लगाए जैसे वह चीनी मीडिया पर लगाने की आदी हो चुकी है।

3. तिब्बत के निर्वासित शासक और सर्वोच्च धार्मिक नेता दलाई लामा तिब्बती जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हैं। इसलिए हम दुनिया भर की लोकतांत्रिक सरकारों और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों से अनुरोध करते हैं कि वे चीन सरकार पर दबाव डालकर उसे दलाई लामा के साथ बातचीत करने और तिब्बती समस्या का एक शांतिपूर्ण और आपसी तौर पर मान्य हल निकालने के लिए प्रोत्साहित करें।

*पत्रकार संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की इस बात के लिए आलोचना की है कि वह ओलंपिक नियमों की अवहेलना करके चीन सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर मनमाने प्रतिबंध लगाने की अनुमति देकर अपने दब्बूपन का प्रदर्शन कर रहा है। चीनी एजेंट टीवी लाइव फुटेज को केवल तभी प्रसारण की अनुमति देंगे जब वे आश्वस्त हो जाएंगे कि इसमें किसी प्रदर्शनकारी या चीन विरोधी नारे वाला बैनर आदि नहीं दिखाया गया।*

## कैमरे की आंख

1. तिब्बती जनता की आजादी की मांग के जवाब में ल्हासा की सड़कों पर उत
2. तिब्बत में चीनी उपनिवेशवाद विरोधी प्रदर्शनों का ताप बीजिंग तक जा पहुंच
3. तिब्बत की माचू काउंटी में 17 मार्च के दिन चीन विरोधी प्रदर्शन करते स्था
4. गांसू प्रांत के कीर्ति मठ को घेरे खड़े चीनी सैनिक और उनके मुकाबले खड़े
5. तिब्बत में चीनी सेना की गोली से मरे 200 से ज्यादा तिब्बती नागरिकों के
6. नई दिल्ली में बीजिंग–ओलंपिक टार्च के जवाब में भारतीय धर्मों के वरिष्ठ प्र
7. तिब्बत में प्रदर्शनों के दौरान शहीदों और स्वतंत्रा संग्रामियों के लिए राजघाट
8. तिब्बती प्रदर्शनों के समर्थन में नई दिल्ली के तिब्बती युवाओं की मोटर साइ
9. तिब्बत में चीनी अत्याचारों की झांकी का मंचन नई दिल्ली के जंतर मंतर प
10. तिब्बत में जनता के चीनी उपनिवेशवादी विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन में दुनि

*(1 से 4 फोटो तिब्बत के अनाम प्रद*

## ♦ आंखों देखी

## आंख से तिब्बत

र उतरे चीनी सैनिक।

पहुंचा। बीजिंग विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करते हुए तिब्बती छात्र।

स्थानीय युवा।

खड़े हुए स्थानीय नागरिक।

ों के लिए नई दिल्ली के राजघाट में सर्वधर्म प्रार्थना सभा में परमपावन दलाई लामा।

रिष्ठ प्रतिनिधि नेताओं ने राजघाट से समांतर सद्भाव–ज्योति यात्रा में भाग लिया।

जघाट पर 17 अप्रैल की प्रार्थना सभा में भारी संख्या में तिब्बतियों ने भाग लिया।

साइकिल रैली को झंडा दिखाते हुए प्रधानमंत्री प्रो. सामदोंग रिंपोछे

तर पर तिब्बती युवाओं ने किया।

दुनिया भर में प्रदर्शन हुए। धर्मशाला में ऐसे एक प्रदर्शन में एक तिब्बती परिवार।

*म प्रदर्शनकारियों द्वारा खींचकर इंटरनेट या मोबाइल से बाहर भेजे गए। 5 से 10 फोटो : विजय क्रान्ति)*

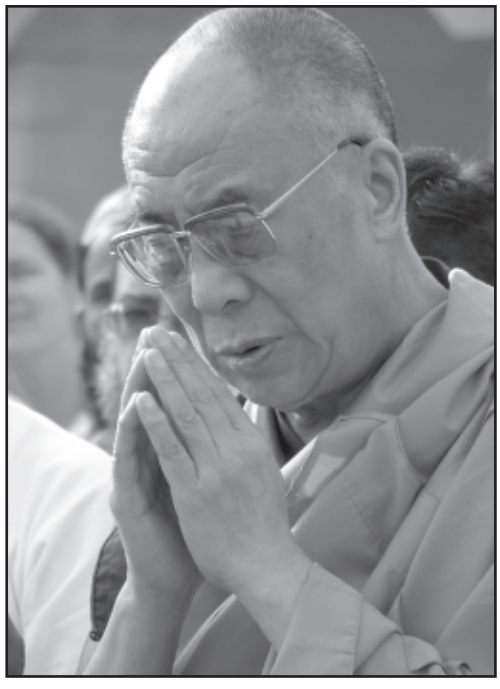

# तिब्बत में चीनी सैनिक कार्रवाई पर दुनिया भर में चिंता व्यक्त की गई

## कुछ महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के वक्तव्य

### आर्कबिशप डेसमंड टूटू, नोबल पुरस्कार विजेता का दलाई लामा को संदेश

''मुझे पता चला है कि चीन ने हिंसा के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया है। यह स्पष्ट है कि चीन आपको नहीं जानता है, लेकिन उसे जानना चाहिए।. .. तिब्बत की जनता चाहती है कि उसकी आवाज़ सुनी जाए। लंबे समय से वे स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने बातचीत तथा मध्यस्थता का रास्ता अपनाया हुआ है। पर अब उन्हें प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। चीन सरकार को उनकी आवाज़ सुननी चाहिए। ''

### सुश्री एंजेला मेर्केल, जर्मनी की चांसलरः

''ल्हासा में अशांति की खबरों से जर्मनी की सरकार चिंतित है। हम चीनी अधिकारियों से अपील करते हैं कि वे प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए संयम और शांतिपूर्ण तरीके का सहारा लें। हम असंतुष्टों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देने की चीन सरकार से अपील करतें हैं।'' जर्मन विदेश मंत्रालय ने चीन सरकार को सलाह दी कि वह ऐसे कदम उठाए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि स्थिति और नहीं बिगड़ेगी और टकराव का शांतिपूर्ण हल निकालने में सहायता मिलेगी।

*''ल्हासा में अशांति की खबरों से जर्मनी की सरकार चिंतित है। हम चीनी अधिकारियों से अपील करते हैं कि वे प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए संयम और शांतिपूर्ण तरीके का सहारा लें। हम असंतुष्टों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देने की चीन सरकार से अपील करतें हैं।'' – एंजेला मेर्केल*

### बराक ओबामा, अमरीकी सीनेटर और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार

''तिब्बती बौद्धभिक्षुओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के मद्देनजर चीनी अधिकारियों द्वारा की जा रही गिरफ्तारियां और उनके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाइयों की खबरों से मैं बहुत ही आहत हूं।''

### निकोलस सरकोजी, फ्रांस के राष्ट्रपति

श्री सरकोज़ी ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भाग न लेने की घोषणा कर चुक हैं। ओलम्पिक खेलों के बहिष्कार के बारे में उन्होंने कहा, ''सभी विकल्प खुले हैं, लेकिन मैं चीनी अधिकारियों से अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभाने की अपील करता हूं।''

### सुश्री कोंडोलीजा राइस, अमरीकी विदेश मंत्रीः

''हम चीन से अपील करते हैं कि उसे अपने नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक और धार्मिक अभिव्यक्ति के दिये गए अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। हम चीन से अपील करते हैं कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार भिक्षुओं और अन्य को तत्काल रिहा करे।''

### नोबल पुरस्कार विजेता छह महिलाओं कस चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओं को खुला पत्रः

''पूरी दुनिया देख रही है, तिब्बती नागरिक अपनी आजादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपलोग परमपावन दलाई लामा के बताये रास्ते पर ही चलेंगे और हिंसक तौर–तरीकों का रास्ता नहीं अपनाएंगे।''

### स्टीफेन हार्पर, कनाडा के प्रधानमंत्रीः

''तिब्बत में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति कनाडा गंभीर रूप से चिंतित है। जब मेरी मुलाकात परमपावन दलाई लामा से हुई थी तब भी उन्होंने अहिंसा और मध्यस्थता को उत्तम मार्ग बताया था। वह हमेशा से ही अहिंसा के पक्षधर रहे हैं। कनाडा चीन से अपील करता है कि वह मानवाधिकारों और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का पूरा सम्मान करे और तिब्बत में उत्पन्न स्थिति पर पार पाने में संयम का परिचय दे।''

**केविन रुड, आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्रीः**

''तिब्बत में हाल के घटनाक्रम बहुत ही दुखद हैं और मैं चीन सरकार से संयम बरतने की अपील करता हूं।... मैं चाहता हूं कि यह असंतोष जल्दी समाप्त हो और इससे आगे जानों की और हानि न हो। हमारा यह मानना है कि यह खुद चीन सरकार के हित में है कि वह तिब्बत की समस्या का एक शांतिपूर्ण और रचनात्मक हल निकाले।''

**ताईवानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्तिः**

''2008 के बीजिंग ओलम्पिक के नाम पर चीन अपने तथाकथित शांतिपूर्ण प्रयासों को सही ठहराने का प्रयास कर रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि लोकतांत्रिक देश ताईवान को लक्ष्य बनाने के लिए वह अपने प्रक्षेपास्त्रों की संख्या में तेजी से बढोतरी कर रहा है। चीन सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को नजरंदाज करती रही है और तिब्बत की जनता के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई को अंजाम देती रही है, जबकि तिब्बतियों की गुस्ताखी बस इतनी है कि वे आजादी और लोकतंत्र के अपने मौलिक अधिकारों की मांग करते आ रहे हैं।''

**डोनाल्ड तुस्क, पोलैंड के प्रधानमंत्री**

श्री तुस्क बीजिंग ओलम्पिक 2008 के उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लेने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने कहा, ''पोलैंड एक औसत देश है। हम पहले पायदान पर पहुंचने की होड़ में शामिल नहीं हैं। लेकिन मेरा फैसला बहुत ही स्पष्ट है। ओलम्पिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान राजनीतिज्ञों की उपस्थिति मुझे अनुचित लगती है।''

**हावर्ड बेरमन, अमेरिकी सांसद**

''इस संकट को ध्यान में रखते हुए चीन सरकार को चाहिए कि तिब्बत के लिए बनाई गई गलत–सलत नीतियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। उसे परमपावन दलाई लामा के साथ सकारात्मक बातचीत भी करनी चाहिए।

**वेन जियाबाओ, चीनी प्रधानमंत्री** का पत्रकारों के सामने बयानः

''इससे इस बात का खुलासा हो जाता है कि 'दलाई लामा के समर्थकों का लगातार यह दावा कि वे आजादी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, शांतिपूर्ण वार्ता के लिए प्रयास कर रहे हैं', कुछ और नहीं झूठ का पुलिंदा मात्र है। ....हमारे पास पर्याप्त तथ्य और अनेक सबूत मौजूद हैं, जिससे साबित होता है कि यह घटना संगठित, पूर्व नियोजित और दलाई लामा गिरोह की साजिश का परिणाम है।'' लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत ब्योरा नहीं दिया।

**लू शुमिन, कनाडा में चीन के राजदूत,**

''दलाई लामा दशकों से झूठ बोलते रहे हैं।''

**टिमोथी ब्रूक,** कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलम्बिया में चीनी मामलों के चर्चित विशेषज्ञ की चीनी राजदूत के बयान पर टिप्पणीः

''यदि मैं राजदूत होता, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते वक्त बहुत ही सतर्क होता। यह बयान न तो ऐतिहासिक रूप से सही है और न ही यह मौजूदा संकट के समाधान का कोई तरीका है।''

*सच्चाई यह है कि लोकतांत्रिक देश ताईवान को लक्ष्य बनाने के लिए वह अपने प्रक्षेपास्त्रों की संख्या में तेजी से बढोतरी कर रहा है। चीन सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को नजरंदाज करती रही है और तिब्बत की जनता के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई को अंजाम देती रही है, जबकि तिब्बतियों की गुस्ताखी बस इतनी है कि वे आजादी और लोकतंत्र के अपने मौलिक अधिकारों की मांग करते आ रहे हैं।*

# तिब्बत मुक्ति–साधना का तूफान पूरे तिब्बत में फैला, दुनिया की आंखें खुलीं

## 10 मार्च, से तिब्बत में उठी जनक्रान्ति और चीनी दमन का तिथिवार विवरण–1

*चीनी उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने के लिए जंगल की आग की तरह फैले इन प्रदर्शनों ने चीन सरकार को सकते में डाल दिया। विश्व जनमत के लिए भी यह एक अनूठा अनुभव था। उनके लिए यह बहुत बड़ी हैरानी की बात थी कि चीन के पचास साल से ज्यादा लंबे अत्याचारों, दमन, नियंत्रण, प्रोपेगेंडा और ब्रेन वाशिंग के बाद भी तिब्बत की जनता के मन में आजादी की अलख पहले की तरह कायम है।*

हर साल की तरह इस साल भी 10 मार्च के दिन तिब्बती जनक्रान्ति की 49वीं वर्षगांठ के मौके पर तिब्बत की राजधानी ल्हासा में चीनी उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। पहला प्रदर्शन केवल सात भिक्षुओं ने किया जिन्हें चीनी पुलिस के पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के पहले से चौकस एजेंटों ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन न केवल ल्हासा के दूसरे हिस्सों में भी फैल गए बल्कि चीन के सिचुआन, गांसू, युन्नान और चिंघाई के ऐसे पचास से ज्यादा हिस्सों तक भी जा पहुंचे जिन्हें तिब्बत पर कब्जे के तुरंत बाद चीन ने तिब्बत से काटकर इन्हें पड़ोसी चीनी प्रांतों में मिला कर हजम कर लिया था। इनमें से कई इलाके ल्हासा से ढाई हजार किमी से भी ज्यादा दूर हैं।

चीनी उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने के लिए जंगल की आग की तरह फैले इन प्रदर्शनों ने चीन सरकार को सकते में डाल दिया। विश्व जनमत के लिए भी यह एक अनूठा अनुभव था। उनके लिए यह बहुत बड़ी हैरानी की बात थी कि चीन के पचास साल से ज्यादा लंबे अत्याचारों, दमन, नियंत्रण, प्रोपेगेंडा और ब्रेन वाशिंग के बाद भी तिब्बत की जनता के मन में आजादी की अलख पहले की तरह कायम है।

चीन सरकार इस बात से भी परेशान थी कि अब तक सभी प्रदर्शनों को वह समय रहते कुचलने में कामयाब रहती थी और तिब्बत के भीतर इस दमन की खबरें सूचना और समाचारों पर सरकारी नियंत्रण के कारण बाहरी दुनिया की आंखों से ओझल रहती थीं। लेकिन इस बार आम तिब्बती प्रदर्शनकारियों और भिक्षुओं के मोबाइल फोन और इंटरनेट ने इन प्रदर्शनों के पूरे विवरण, तस्वीरें और वीडियो फुटेज दुनिया भर के अखबारों और टीवी चैनलों तक पहुंचा कर तिब्बत की असली हालत को बेनकाब कर दिया। चीन सरकार के हर तरह के दमन के बावजूद प्रदर्शनों का यह सिलसिला पूरे मार्च और अप्रैल में चलता रहा। बौखलायी हुई चीन सरकार की गोलियों से अब तक 209 से ज्यादा तिब्बती प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं।

तिब्बत की निर्वासन सरकार की विभिन्न एजेंसियां और संगठन इन प्रदर्शनों के बारे में विस्तृत विवरण इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इस दिशा में श्री **तेनजिन सोनम गोंसार** और **श्री कुनसांग दोरजी** ने अब तक जो विवरण तैयार किया है उस पर आधारित यह रिपोर्ट हम 'तिब्बत देश' के पाठकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अंक में उपलब्ध स्थान की सीमा को देखते हुए हम इस विवरण का पहला अंश यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी विवरण मई अंक में पेश किया जाएगा।

### 10 मार्च, 2008

**ल्हासा** – तिब्बती जनक्रान्ति की 49वीं वर्षगांठ के मौके पर ल्हासा में प्रदर्शन हुआ। राजधानी ल्हासा के बारखोर क्षेत्र में सात भिक्षु शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उनके हाथों में तिब्बत के तीन राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे थे। जैसे ही भिक्षुओं ने नारे लगाने शुरू किये, आम नागरिक उनके समर्थन के लिए प्रदर्शन में जुट गये। लेकिन इस प्रदर्शन के गति पकड़ने से पहले ही चीनी पुलिस और पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो (पीएसबी) के खुफिया एजेंट वहां पहुंच गए। प्रदर्शनकारी भिक्षुओं को गिरफ्तार कर लिया। जब लोगों ने विरोध किया तो उनकी भरपूर पिटाई की गयी।

**तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से बाहर चिंघाई प्रांत की युशुल क्येगुदो काउंटी**

चीन के स्थानीय पब्लिक सिक्यूरिटी ब्यूरो (पीएसबी) के अधिकारियों ने नौ मार्च को युशुल काउंटी के अनेक घरों में छापे मारकर परमपावन दलाई लामा की प्रतिबंधित तस्वीरें बरामद कीं। दो परिवारों को दलाई लामा की तस्वीरें रखने के लिए पांच–पाच सौ युआन जुर्माना लगाया गया। वहां से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले दिन पूरे इलाके में दीवारों पर तिब्बत की आजादी की मांग के पर्चे चिपके मिले।

**चिंघाई प्रांत की मांगरा काउंटी**

चिंघई प्रांत में आम्दो की मांगरा काउंटी में भी 10 मार्च को दूसरी घटना हुई। मांगरा काउंटी की पीपुल्स आर्म्ड पुलिस के जवानों ने लुत्सांग मठ के 137 भिक्षुओं और कम से कम 200 सामान्य तिब्बतियों को उस वक्त रोक दिया जब वे लोग काउंटी के एसेम्बली हॉल के बाहर एकत्रित हो रहे थे। वहां एक सरकारी प्रायोजित शो चल रहा था। लेकिन तिब्बतियों के विरोध की वजह से शो को रोकना पड़ा। बाद में भिक्षुओं और तिब्बती प्रदर्शनकारियों ने 'दलाई लामा जिन्दाबाद' और 'दलाई लामा तिब्बत आएं' के नारे लगाने शुरू कर दिये।

**बारखोर और सेरा मठ (ल्हासा)–**

ल्हासा के बारखोर इलाके में 10 मार्च को पंद्रह

भिक्षुओं के एक दल ने त्सुगलाखांग मंदिर से तिब्बत के समर्थन में शांतिपूर्ण पदयात्रा शुरू की, जिसमें बाद में दो और नागरिक जुड़ गये। वे लोग तिब्बत की आजादी की मांग के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे और पर्चे बांट रहे थे। उनके हाथों में तिब्बत के प्रतिबंधित राष्ट्रीय ध्वज भी लहरा रहे थे। थोड़ी ही दूरी की पदयात्रा के बाद वहां तैनात पीएसबी के अधिकारियों ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी पिटाई भी की। इस घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त सैन्य बल तैनात कर दिये गए ओर लोगों को किसी विरोध प्रदर्शन से दूर रहने की चेतावनी दी।

ग्यारह मार्च को करीब 200 चीनी सैनिकों ने सेरा मठ के उन सैकड़ों भिक्षुओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े जो अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। इनलोगों ने तिब्बत की आजादी के समर्थन में नारे भी लगाए। सेरा और द्रेपुंग मठों में उस वक्त अत्यधिक तनाव पैदा हो गया, जब चीन की सशस्त्र पुलिस ने इन मठों को सील कर दिया और वहां तिब्बतियों के आने–जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में पंद्रह प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किये जाने की खबर है, लेकिन यह पता नहीं चल पाया है कि उन्हें कहां ले जाया गया है।

**द्रेपुंग मठ (ल्हासा)**

10 मार्च की शाम को राजधानी ल्हासा के बाहर लगभग पांच किलोमीटर दूर स्थित द्रेपुंग मठ के तीन सौ भिक्षुओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उन्होंने ल्हासा के बारखोर इलाके की ओर कूच किया। लेकिन उन्हें चीन के सशस्त्र बलों ने ल्हासा पहुंचने से पहले ही रोक दिया। पीएसबी के अधिकारियों ने कई भिक्षुओं को गिरफ्तार कर लिया।

**पालुंग, बायान काउंटी (चिंघाई प्रांत)**

एक अन्य घटना में कम से कम 20 स्थानीय चीनी अधिकारियों ने दित्सा मठ के भिक्षुओं की बैठक बुलाई थी। हालांकि परमपावन दलाई लामा की तस्वीरें लिए कम से कम 70 भिक्षुओं ने बैठक का बहिष्कार किया और तिब्बत की आजादी के समर्थन में नारेबाजी की। बाद में ये भिक्षु 'सांगसोल प्रार्थना' में भाग लेने के लिए मठ के पीछे स्थित पहाड़ी की ओर निकल पड़े। उस दिन कम से कम 400 लोग प्रार्थना सभा के लिए जमा हुए थे। लेकिन इस इलाके से किसी भी तिब्बती के गिरफ्तार किये जाने की कोई सूचना नहीं है।

**पूर्व राजनीतिक कैदियों के घरों पर छापे**

10 मार्च से पहले ही ल्हासा में पूर्व राजनीतिक

रेबकांग मठ में तिब्बती भिक्षुओं का प्रदर्शन : बुलंद हौसले

कैदियों के घरों पर चीनी पीएसबी द्वारा छापे मारे जाने की खबरें आती रहीं। पीएसबी एजेंटों का सबसे ज्यादा ध्यान घरों से दस्तावेज और सीडी आदि ढूंढने पर था। चीनी अधिकारियों ने पूर्व राजनीतिक कैदियों के घरों में उनके कम्प्यूटर, फोन और इंटरनेट कनेक्शनों जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी खासतौर पर जांच की।

**सांगचू काउंटी, गांसू प्रांत**

ऐसी खबर है कि चीनी पुलिसकर्मियों ने सांगचू काउंटी स्थित लाबरांग ताशीखेल मठ से तिब्बत की आजादी वाले परचे पकड़े।

**कारज़े काउंटी, सिचुआन प्रांत**

तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की कारजे काउंटी में भी 10 मार्च को तिब्बतियों ने पोस्टर और परचे चिपकाए। लेकिन इसे लेकर पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पायी।

**11 मार्च, 2008**

**सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द और तिब्बत यूनिवर्सिटी, ल्हासा में प्रतिबंध लागू**

ल्हासा नगर प्रशासन ने विभिन्न सरकारी विभागों के उन सभी तिब्बती कर्मचारियों को तुरंत काम पर लौटने का फरमान जारी किया जो छुट्टियां काट रहे थे। साथ ही छुट्टियां लेने पर पाबंदी भी लगा दी गयी। ल्हासा में तिब्बत यूनिवर्सिटी सहित विभिन्न संस्थानों के छात्र–छात्राओं के बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गयी।

**दाबपा काउंटी,** सिचुआन प्रांत

*ग्यारह मार्च को करीब 200 चीनी सैनिकों ने सेरा मठ के उन सैकड़ों भिक्षुओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े जो अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। इनलोगों ने तिब्बत की आजादी के समर्थन में नारे भी लगाए। सेरा और द्रेपुंग मठों में उस वक्त अत्यधिक तनाव पैदा हो गया, जब चीन की सशस्त्र पुलिस ने इन मठों को सील कर दिया।*

ल्हासा में प्रदर्शनों के जवाब में चीनी सैनिक : भयभीत उपनिवेशवाद

दाबपा काउंटी में तिब्बतियों ने चीनियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किये। प्रदर्शनकारियों को तितर–बितर करने के लिए चीन की सशस्त्र पुलिस द्वारा चलाई गयी गोलियों के कारण तीन तिब्बती नागरिकों की मौत हो गयी और कम से कम दस लोग घायल हुए। चीनी पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार देने का निर्देश दिया गया था।

*'तिब्बती महिला दिवस' के मौके पर चुत्सांग भिक्षुणी मठ से करीब एक सौ भिक्षुणियों ने ल्हासा के बारखोर की ओर कूच किया। लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन 13 मार्च की सुबह उन्होंने फिर से अपना मार्च शुरू किया और उन्हें अपने मकसद में कामयाबी मिल गयी।*

**12 मार्च, 2008 गंदेन मठ को सील किया**

भिक्षुओं के विरोध प्रदर्शन के कारण 11 मार्च दोपहर से ही चीन की सशस्त्र पुलिस ने ल्हासा शहर से 50 किलोमीटर दूर गंदेन मठ को सील कर दिया था और चारो ओर पहरा बिठा दिया गया। 12 मार्च के दिन पुलिस के इस पहरे को और सख्त कर दिया गया।

**चुत्सांग भिक्षुणी मठ से कूच**

12 मार्च को तिब्बत में हर साल तिब्बती महिलाओं के उस आंदोलन को याद किया जाता है जो उन्होंने 1959 में चीन सरकार के खिलाफ शुरू किया था। 'तिब्बती महिला दिवस' के इस मौके पर इस बार चुत्सांग भिक्षुणी मठ से करीब एक सौ भिक्षुणियों ने ल्हासा के पश्चिमी क्षेत्र से बारखोर मार्ग की ओर कूच किया। लेकिन उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने उस दिशा में बढ़ने से रोक दिया। बाद में पुलिस ने भिक्षुणिओं को जबरन अपने मठ की ओर वापस भेज दिया।

**13 मार्च, 2008**

लेकिन 13 मार्च की सुबह ही इन भिक्षुणियों ने चुत्सांग मठ से ल्हासा के खारबोर की ओर फिर से अपना मार्च शुरू किया और उन्हें अपने मकसद में कामयाबी मिल गयी। इन भिक्षुणियों ने ल्हासा में लगातार हो रहे प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया।

अधिकारियों ने स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों को प्रदर्शनों में भाग न लेने की चेतावनी जारी की। ल्हासा स्थित स्थानीय विदेशी ब्यूरो कार्यालय ने गैर सरकारी संगठनों, खासकर जिनके सम्पर्क दुनिया के अन्य देशों से भी हैं, को विशेष चेतावनी दी कि तिब्बत में विरोध प्रदर्शन के बारे में किसी तरह की जानकारी दुनिया के अन्य देशों या संगठनों के साथ बांटी नहीं जाए, अन्यथा दोषी व्यक्ति या एनजीओ के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है और संगठन को बंद भी किया जा सकता है। ब्यूरो कार्यालय ने यह भी कहा है कि उसने तिब्बत में विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। एनजीओ संगठनों को यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि उसने ई–मेल या इंटरनेट के जरिये तिब्बत की मौजूदा स्थिति की जानकारी अन्यत्र भेजी तो उनके खिलाफ कठोर कदम उठाये जाएंगे।

**14 मार्च, 2008 रामोचे मंदिर पर पुलिस का घेरा**

ल्हासा से मिली खबरों में इस बात की पुष्टि हो गयी है कि रामोचे मठ के भिक्षुओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के कारण ल्हासा में ज्यादातर हिस्से के चारों ओर पीपुल्स आर्म्ड पुलिस ने घेरा डाल दिया।

रात्रि ग्यारह बजे चीनी अधिकारियों ने ल्हासा में स्कूल, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने की घोषणा कर दी। शहर में तिब्बती प्रदर्शनों को दबाने के लिए पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने और प्रदर्शनकारियों के मारे जाने और घायल होने के समाचार लगातार आते रहे।

**15 मार्च, 2008 : मौतों का सिलसिला जारी**

केवल ल्हासा में ही अभी तक 30 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि अपुष्ट खबरों के अनुसार 100 से अधिक लोगों की जानें गयी हैं।

सूत्रों ने बताया कि ल्हासा के उत्तर में सेरा मठ के निकट न्यांग–ड्रेन में 200 से अधिक लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ल्हासा के पूरब में कर्मा कुनसांग में भी तिब्बतियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए।

गांसू प्रांत के लाबरांग ताशीखेल मठ के पास भी बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें ज्यादातर आम नागरिक ही शामिल थे। चीन की सशस्त्र पुलिस ने प्रदर्शनकारियों में से चार को हिरासत में लिया।

**लाशों से भरा ट्रक** : एक विश्वसनीय सूत्र ने इस बात की पुष्टि की है कि शवों से लदे एक सैन्य ट्रक को ल्हासा नगर निगम के अंतर्गत तोएलुंग काउंटी की ओर जाते देखा गया। सिचुआन प्रांत के लिथांग में दो प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।

**6 हजार लोगों का प्रदर्शन** : इसी प्रांत में लाबरांग आम्दो न्गाबा में पांच से छह हजार लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारी तिब्बत की आजादी के अलावा परमपावन दलाई लामा की तिब्बत वापसी की मांग भी कर रहे थे। ल्हासा नगर निगम के तहत फेम्पो हुंड्रूप काउंटी में भी भिक्षुओं और आम तिब्बतियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जबकि ल्हासा से 50 किलोमीटर गंदेन मठ के चारो ओर चीनी सुरक्षाकर्मियों ने घेरा डाले रखा था।

**शिगात्से में गोलीबारी** : शिगात्से काउंटी स्थित ताशी ल्हुंपो मठ में पुलिस द्वारा गोलीबारी की खबर है। इस मठ के पीछे से कम से कम 40 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। केवल ल्हासा में ही 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह संख्या अधिक भी हो सकती है क्योंकि जिनलोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें तिब्बत में दूर–दूर की जेलों में ले जाया गया है।

तिब्बत में प्रदर्शनों के दौरान किसी कारण से मौजूद विदेशी मीडिया सहित सभी मीडियाकर्मियों से पूछताछ की गयी और ऐसी खबरें हैं कि मीडियाकर्मियों के वीडियो फुटेज, तस्वीरें आदि नष्ट कर दी गयीं या जब्त कर ली गयीं।

**चीनी अधिकारियों की मांग : आत्मसमर्पण करें प्रदर्शनकारी**

चीन में तिबेतन हायर पीपुल्स कोर्ट ऑफ चाईना ने शनिवार को एक नोटिस जारी किया, जिसमें सोमवार की रात तक तिब्बती प्रदर्शनकारियों को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी गयी। कोर्ट ने यह भी कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नरमी बरती जाएगी।

नोटिस में यह भी कहा गया कि जो प्रदर्शनकारी आत्मसमर्पण करेंगे और अन्य प्रदर्शनकारियों के बारे में सूचना उपलब्ध कराएंगे, उन्हें सजा से मुक्त कर दिया जाएगा, जबकि प्रदर्शनकारियों को पनाह या आश्रय देने वालों को सजा दी जाएगी।

**1 मार्च, 2008 : ल्हासा में 80 मौतें**

तिब्बत में मौजूद विश्वस्त सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि 14 मार्च, 2008 को केवल ल्हासा में ही कम से कम 80 लोगों की मौतें हुई हैं। एक इन

लांझू के स्कूल में युवा तिब्बती प्रदर्शनकारी : गुलामी से मुक्ति के लिए

सूत्रों ने बताया कि अनेक लाशों को ल्हासा स्थित सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के कार्यालय के समक्ष यों ही ढेर लगाकर रखा गया है।

**गांसू के कीर्ति मठ में अभूतपूर्व प्रदर्शन** : आज सुबह साढे नौ बजे आम्दो न्गापा प्रांत के कीर्ति मठ के एक हजार से अधिक बौद्धभिक्षु कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए निकल पड़े और कम से कम एक हजार आम तिब्बती भी उनके साथ हो लिए। इस प्रदर्शन से पहले चीनी सेना ने इस मठ को पूरी तरह सील कर रखा था।

**कीर्ति मठ 15 लाशें और आंखों देखा हालः** 17 मार्च के दिन भारत के धर्मशाला में एक अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों ने मोबाइल फोन पर कीर्ति मठ में एक भिक्षु से बातचीत की। इस भिक्षु ने पत्रकारों को बताया कि प्रदर्शनकारियों पर चीनी सेना और पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और बंदूकों से गोलियां चलाई गयीं। इस भिक्षु ने आंखों देखा विवरण देते हुए बताया कि उस समय जहां वह खड़ा है वहां पुलिस की गोली से मारे गए 15 तिब्बतियों की लाशें पड़ी हैं और मठ को सेना के ट्रकों ने घेरा हुआ है।

**घायलों के इलाज पर पाबंदी** : पता चला है कि चीनी सेना की गोलियों से घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज करने पर पूरे तिब्बत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। अस्पतालों और डाक्टरों को निर्देश जारी किए गए कि ऐसे लोगों का इलाज करने से पहले स्थानीय पुलिस के हाथ उन्हें सौंप दिया जाए। इस कारण सैंकड़ों घायल प्रदर्शनकारियों की जान पर खतरा बना हुआ है।

चीन के उच्च अधिकारियों ने तिब्बती अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया कि कोई भी तिब्बती

*17 मार्च के दिन धर्मशाला में एक अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों ने मोबाइल फोन पर कीर्ति मठ में एक भिक्षु से बातचीत की। इस भिक्षु ने` बताया कि उस समय जहां वह खड़ा है वहां पुलिस की गोली से मारे गए 15 तिब्बतियों की लाशें पड़ी हैं और मठ को सेना के ट्रकों ने घेरा हुआ है।*

नागरिक प्रदर्शन में भाग नहीं ले। उनके आंदोलन को प्रतिबंधित कर दिया गया। लोगों के अपने घर से निकलने और वापस आने पर हस्ताक्षर करने की शर्त भी लगा दी गयी ताकि उनके आने जाने का हिसाब रखा जा सके।

**चिंघाई में व्यापक प्रदर्शन** : चिंघाई प्रांत के राग्ये मठ के भिक्षुओं ने भी प्रदर्शन किया। इसी प्रांत के कान्हलो में स्थित कुछ स्कूलों में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। कान्हलो के माचू काउंटी में छात्रों, आम तिब्बतियों और तिब्बत के पूर्व अधिकारियों ने एक साथ मिलकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन स्थल से कई प्रदर्शनकारी छात्रों को गिरफ्तार किया गया।

चिंघाई प्रांत के रेबगांग काउंटी स्थित रोंगपो गोनचेन मठ के भिक्षुओं ने मठ के सामने स्थित परिसर में भी जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के मंसूबों को कुचलने के लिए पीएसबी के अधिकारी वहां पहुंचे, लेकिन मठ के प्रधान भिक्षु ने बातचीत के जरिये स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बातचीत के बाद पीएसबी अधिकारी संभवतः लौट गये। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। ल्हासा स्थित पांगसा मठ के भिक्षुओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया, जिनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन तिब्बती नागरिकों के जोरदार दबाव के कारण उनलोगों को बाद में रिहा कर दिया गया।

**गांसू में छात्रों की भूख हड़तालः** उधर गांसू प्रांत के लांझऊ नगर स्थित पश्चिमोत्तर नेशनलिटीज यूनिवर्सिटी में करीब 500 तिब्बती छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थानीय समयानुसार चार बजे शाम से भूख हड़ताल शुरू कर दी। सिचुआन प्रांत के लिथांग में भी आज भिक्षुओं और आम नागरिकों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। अगले तीन दिनों तक सभी स्कूलों, दुकानों और कार्यालयों को बंद करा दिया गया। 17 मार्च को बड़ी संख्या में पुलिस और सेना के जवानों को इलाके में गश्त करते देखा गया।

### 17 मार्च, 2008ः गोंगकार में प्रदर्शन

ल्हासा से 70 किलोमीटर दूर मेल्द्रो गोंगकार काउंटी स्थित पांगसा और अन्य मठों के भिक्षुओं के नेतृत्व में हजारों प्रदर्शनकारियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया, जिसे नियंत्रित करने के लिए पीपुल्स आर्म्ड पुलिस के जवान सात ट्रकों में भरकर आए। लेकिन वे आंदोलनकारियों को नियंत्रित कर पाने में असफल रहे। उन पुलिसकर्मियों की मदद के लिए पीएपी के और अधिक जवान भेजे गये। इलाके में सभी स्कूल, दुकानें और कार्यालय बंद रहे।

उधर चिंघाई प्रांत के युलगान काउंटी स्थित त्सांग मठ के करीब 500 भिक्षुओं ने सुबह दस बजे से अपना आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों ने मठ के गुम्बद पर तिब्बत के राष्ट्रीय ध्वज फहराए। उन्होंने परमपावन दलाई लामा की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन किये। यहां भी पीएपी के जवान स्थिति पर नियंत्रण के लिए पहुंचे, लेकिन काफी समय तक प्रदर्शन जारी रहा। गांसू प्रांत के माचू काउंटी में भी कुछ छात्रों के एक समूह ने प्रदर्शन किया, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

द्रीरु काउंटी के हारथांग मठ में पेला तुल्कू नामक अवतारी लामा को फरवरी के अंत में धार्मिक प्रवचन करना था, लेकिन स्थानीय चीनी प्रशासन के नुमाइंदों ने इसकी अनुमति प्रदान नहीं की जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय तिब्बती नागरिकों और चीनी नुमाइंदों के बीच झड़प हो गई। तीन मार्च 2008 को चीनी प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण के लिए 'कार्य दल' के और सदस्यों को वहां भेज दिया। बाद में 18 से 30 वर्ष के सभी तिब्बती प्रदर्शनकारियों को 'देशभक्ति की पुनर्शिक्षा' में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया गया।

इसके विरोधस्वरूप 18 मार्च को नागचू और ल्हासा को जोड़ने वाली सड़कों को प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह बंद कर दिया। नागचू में बाहर से आकर रहे लोगों को वहां से निकल जाने को मजबूर कर दिया गया। नागचू के प्रत्येक परिवार के हर पुरुष का नाम एकत्रित किया गया।

**तोएलुंग में जोरदार प्रदर्शन** : स्थानीय समयानुसार करीब तीन बजे तोएलुंग काउंटी के ध्रिंगखा मठ के साथ भिक्षुओं ने सादे वेश में देचेन शहर की ओर जाते वक्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहां तैनात पुलिसकर्मी उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके और अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा। पुलिस बल की जोर जबर्दस्ती को देखते हुए स्थानीय तिब्बती भी भिक्षुओं के साथ हो लिए। आंदोलन का स्वरूप और प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ते देखकर पीएपी के जवानों को बुलाना पड़ा, जिन्होंने करीब 30 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ बहुत ही बेरहमी से व्यवहार किया गया। खाखोग मारथांग काउंटी के तिब्बती छात्रों ने भी अपने स्कूल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। चीनी अधिकारी उन्हें रोक पाने में असमर्थ रहे और प्रदर्शनकारियों ने काउंटी मुख्यालय तक मार्च किया। यहां 30 विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ जमकर मारपीट की गयी।

*(अगले अंक में जारी.)*

*उधर चिंघाई प्रांत के युलगान काउंटी स्थित त्सांग मठ के करीब 500 भिक्षुओं ने सुबह दस बजे से अपना आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों ने मठ के गुम्बद पर तिब्बत के राष्ट्रीय ध्वज फहराए। उन्होंने परमपावन दलाई लामा की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन किये। यहां भी पीएपी के जवान स्थिति पर नियंत्रण के लिए पहुंचे, लेकिन काफी समय तक प्रदर्शन जारी रहा। गांसू प्रांत के माचू काउंटी में भी कुछ छात्रों के एक समूह ने प्रदर्शन किया, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।*